प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
13.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15.00बजे

गृह मंत्रालय–केंद्रीय सहायता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित हिमाचल प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के लिए एक हजार नौ सौ बारह करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए 2 सौ 88 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष–एसडीआरएफ में जारी की गई उन धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने एस.डी.आर.एफ. के तहत 28 राज्यों को बीस हजार सात सौ पैंतीस करोड़ रुपये से अधिक के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तहत 21 राज्यों को तीन हजार छह सौ 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में पैट्रोल डीजल व एल.पी.जी. की पर्याप्त मात्रा है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में रसोई गैस और व्यवसायिक सिलेंडरों की भी कोई कमी नहीं है और राज्य सरकार ने इसके लिए नागरिक आपूर्ति के तहत स्टॉक जारी किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि एल.पी.जी. गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और सभी उपायुक्तों, खाद्य आपूर्ति विभाग व तेल कंपनियों को ताजा स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संजय गुप्ता ने कहा कि एल.पी.जी. की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है।

इंदू गोस्वामी

केंद्र सरकार ने हिमाचल में पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान एक सौ 21 करोड़ 90 लाख रुपये का बजट आबंटित किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में सांसद इंदू गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि में एक सौ 10 करोड़ 66 लाख रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी और 11 करोड़ 24 लाख रुपये राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत देश में लगभग 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में गर्म पौष्टिक खाना प्रदान किया जा रहा है।

बागवानी मंत्री

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में एच.पी. शिवा परियोजना बागवानी को नई दिशा प्रदान कर रही है और इसके तहत भूमि के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने मंडी ज़िले के सरकाघाट उपमंडल के तहत भांबला और बही में एच.पी. शिवा क्लस्टर का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया। बागवानी मंत्री ने सिंचाई टैंक, मोटर व ड्रिप सिंचाई प्रणाली का जायजा भी लिया। जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के बागवानों से शिवा परियोजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आहवान किया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि विभाग में कई नए सुधार किए जा रहे हैं और अनेक प्रमाण पत्रों के अलावा जमाबंदी व ततीमा भी ऑनलाईन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है।

मटर

सोलन ज़िले में मटर की फसल में रोग लगने से किसान चिंतित है और उनकी आर्थिकी पर विपरित असर पड़ रहा है। इस बार कम वर्षा होने से मटर की फसल में सुखन रोग लग गया है और किसानों की लगभग 50 फीसदी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने बताया कि मटर की फसल 25 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है जो बहुत कम है।